

एक विचार कर्मचारियों के बारे में |

यह हमारे देश हिन्दुस्तान को एकजुट करने का एक प्रयास है |

हम देश के प्रत्येक कर्मचारी से यह अनुरोध करते हैं कि वह इस कार्य के लिए आगे आए और हमारा सहयोग करें |

वर्तमान स्थिति :

हमारे देश में कर्मचारी बहुत ही दबाव में कार्य करते हैं और विशेष तौर पर जो उच्च स्तर पर कार्य करने वाले | इकनॉमिक टाइम्स के अनुसार 2015 में ऐसे 2000 से अधिक कर्मचारियों के मन में यह विचार आया कि वह आत्महत्या कर लें |

प्र : यह वर्तमान स्थिति कैसे परिवर्तित की जा सकती है ?

उ : अगर हमारा देश हिन्दुस्तान स्वर्ग कैसे बन सकता है, के प्रावधानों को लागू करा दें | कर्मचारियों से संबंधित एक प्रस्ताव साथ दिया गया है |

प्र : इन कार्यों के लिए धन/पैसा कहां से आएगा ?

उ : आयकर समाप्त होने के बाद सरकार के पास निम्न प्रकार से आएगा :

- उत्पाद शुल्क, बिक्री कर व सेवा कर लगने पर देश में करों की आमद बहुत बढ़ जाएगी और सिक्के चलने पर चोरी करना असंभव हो जाएगा |
- समता कर लगने पर जो व्यक्ति व्यापार या परियोजनाएं / प्रोजेक्ट्स नहीं कर पाएंगे उन पर यह कर लगेगा, उसकी आमद |
- सरकार 0.01% सालाना ब्याज पर ऋण / लोन ले सकती है और यह 10, 20, 50..... 1000 लाख करोड़, जितना मर्जी हो लिया जा सकता है और यह केवल किताबी एंट्री / लेखा-जोखा/ चलन (Circulation) के अतिरिक्त कुछ भी नहीं और यह धन सरकार ने कभी वापिस भी नहीं करना |

इस प्रकार सरकार के पास कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी |

प्र : कर्मचारियों का जीवन बेहतर कैसे हो सकता है ?

उ : सप्ताह में 28 घंटे कार्य हो और कार्य सप्ताह में सातों दिन हो | प्रत्येक कर्मचारी को 2.5 प्रतिशत सालाना की दर से जितने वर्ष कार्य किया है के अनुसार पेंशन का प्रावधान हो या 50% इन दोनों में जो अधिक हो | फैमिली पेंशन की भी व्यवस्था हो जो 50% से 75% वेतन के बराबर हो | जो पूर्व कर्मचारी हैं उनको पेंशन मिले जो कि वर्तमान ढांचे (कैडर) में उस तरह के कर्मचारी की है | पेंशन देना सरकार की जिम्मेवारी हो और सभी सरकारी व गैर सरकारी कर्मचारियों को यह उपलब्ध हो |

हिजड़ो, वेश्याओं, गटर साफ करने वाले, मैला ढोने वाले के लिए विशेष प्रबंध किए जाएं क्योंकि उनका जीवन बहुत ही दयनीय है |

प्र : आप इस कार्य में कैसे सहयोग कर सकते हैं?

उ : जागरूकता को फैलाकर |

प्र : जागरूकता कैसे फैलाई जा सकती है ?

उ : जिस व्यक्ति को भी आप जानते हैं, आप से संबंधित है या नहीं है, नहीं जानते हैं आप उनको ईमेल के द्वारा या अन्य साधन जैसे की एस.एम.एस. (SMS) फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप या अपने व्यक्तिगत संपर्क से यह कार्य कर सकते हैं ।

यह विचार पूर्ण गुरु श्री चन्द्रमोहन जी के हैं जो कि परमात्मा के प्रतिनिधि हैं और इस समय विश्व परिवर्तन के लिए धरती पर हैं ।

हम निश्चित हैं कि यह कार्य बहुत जल्द..... संपन्न होगा ।

श्री परमधाम, मेरठ

वेबसाइट के लिए : www.solutionoflife.in

एक प्रस्ताव कर्मचारियों के लिए ।

प्रिय देशवासियों,

वर्तमान में जो हालात कर्मचारियों के हैं, क्या आप चाहते हैं कि उसका कोई समाधान निकले ? उसके लिए एक मजबूत प्रजातंत्र का होना अनिवार्य है और यह समाधान तब निकल सकता है :

जबकि राजनीतिक सुधार, पुलिस के सुधार व न्यायिक सुधार हो..... जो संलग्न किए गए हैं:-

एक कर्मचारी के लिए :

1. सप्ताह में एक कर्मचारी के लिए 28 घंटे कार्य हो और सप्ताह में सातों दिनों कार्य हो इससे हमारा देश चिंता मुक्त होगा, तनाव / टेंशन मुक्त होगा ।
2. **पेंशन** प्रत्येक व्यक्ति को 5000 रुपए महीना कम से कम पेंशन मिले जो किसी भी व्यक्ति को 60 वर्ष पूरा करने पर व जिनके बच्चे विकलांग हैं उनके लिए है यह आयु सीमा 55 वर्ष की हो । मान लीजिए पुरे देश में 20 करोड़ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पेंशन की आवश्यकता है जोकि एक लाख करोड़ प्रति मास हुआ, साल में 12 लाख करोड़, हम इसे 25 लाख करोड़ मानकर चलते हैं । यह धन सब के द्वारा खर्च होगा जिससे रोजगार के अवसर, करों की आमद व देश में कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी । सरकार यह धन 0.01 % सालाना ब्याज पर ले सकती है जो कभी वापस भी नहीं होना । प्रत्येक सरकारी व गैर-सरकारी कर्मचारी के लिए 2.5 % सालाना कार्य करने पर जितने वर्ष कार्य किया गया है उसके अनुसार उसको पेंशन मिले जो कम से कम उसके वेतन का 50% हो । **अगर किसी ढांचे (कैडर) में यह पेंशन पीछे मिला हो वह वर्तमान में उस ढांचे (कैडर) में वेतन के अनुसार प्राप्त हो ।**
3. **फैमिली पेंशन** का भी प्रावधान हो जोकि वेतन का 50% से 75% हो और जो परिवार में कितने सदस्य हैं उस पर निर्भर करें ।
4. **बेरोजगारी भत्ते** का प्रावधान हो जो कि कम से कम 5000 रुपए प्रति मास हो और हर 6 महीने में यह कम होता जाए जोकि $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$ हो और इसे निखट्टू भत्ता / अलाउंस कहा जाए । जो कर्मचारी कार्य करते हुए बेरोजगार हो गए हैं उनको 2.5 प्रतिशत सालाना, जितने वर्ष कार्य किया है के अनुसार यह भत्ता मिले जो कम से कम उसके वेतन का 50% हो ।
जब कोई समाज/ देश आगे बढ़ रहा होता है तो उसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कहलवाना चाहेगा और उससे देशवासी प्रोत्साहित होंगे ।
5. **हिजड़ी, गटर साफ करने वाले, मैला ढोने वाले व वेश्याओं के लिए एक विशेष प्रबंध किया जाए जिससे उनके लिए रोजगार व पेंशन का प्रावधान हो सके ।**

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सुधार हो और उनको लागू भी किया जाए :-

1. आयकर समाप्त हो जिससे प्रत्येक व्यक्ति भय मुक्त व चिंता मुक्त होगा।
नोट : जो व्यक्ति नकदी या विदेशी विनिमय बैंक में जमा कराएँ उसके विपरीत किसी भी कानून के अंतर्गत किसी भी प्रकार का दीवानी व फौजदारी मुकद्दमा ना चलाया जाए जिससे प्रत्येक व्यक्ति एक नया अध्याय आरंभ कर सके।
2. प्रत्येक व्यक्ति को 0.01% सालाना ब्याज पर आसानी से ऋण /लोन उपलब्ध हो और उस व्यक्ति को मिले जिसके पास योग्यता या क्षमता या सामर्थ्य या शिक्षा या कोई विशेष गुण हो और यह ऋण /लोन निश्चित समय में मिले और नए लोगों को भी उपलब्ध हो (एक करोड़ रुपए के ऋण /लोन पर साल का 1000 रुपए ब्याज)।
3. देश में केवल तीन कर हो उत्पाद शुल्क, विक्री कर व सेवा कर और वह भी अनुपातिक और अधिकतम दर 10% हो। अनुपातिक कर नए व्यापारियों के लिए वरदान सिद्ध होगा।
4. आय की सीमा और संपत्ति की सीमा देश की उन्नति व प्रगति के लिए। इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता व सामर्थ्य के अनुसार अच्छे से अच्छा कमाएगा और रखेगा। लेकिन जिस व्यक्ति के पास कम योग्यता/ सामर्थ्य है, उस व्यक्ति को रोजमर्रा जीवन की आवश्यकताएं आसानी से पूर्ति हो सकें।

प्रत्येक व्यक्ति को 5000 रुपए प्रति महिना पेंशन मिले। जिनके पास आमदनी का कोई भी साधन नहीं है और आयु एक सीमा से ऊपर है। यह सुविधा सरकारी व अन्य वेतन भोगियों को भी उपलब्ध हो। इसमें 2.5% प्रत्येक वर्ष नौकरी का पूरा करने पर या 50% वेतन का, दोनों में जो भी अधिक हो वह उपलब्ध हो और यह उस व्यक्ति की जो आखरी तनखाह थी उसको वर्तमान के अनुसार प्राप्त हो। फैमिली पेंशन का भी प्रावधान हो जो वेतन का 50% से 75% हो और वह उस व्यक्ति के परिवार के सदस्यों की सीमा पर निर्भर करें। इसी प्रकार बेरोजगारी भत्ता भी उपलब्ध हो।

इन सीमाओं के लगने पर एक अमीर आदमी और भी अमीर हो जाएगा (यह लाभ उसे आयकर समाप्त होने के बाद प्राप्त होगा) और वह जब तक अमीर रहेगा जब तक की वह देश के लिए कार्य करता रहेगा यानि व्यापार में अपना योगदान दे रहा है या आधारीक संरचना /इंफ्रास्ट्रक्चर/ धार्मिक/ कल्याण व समाजिक कार्यों में अपना धन लगा रहा है अन्यथा उसे समता कर देना होगा जिसका वर्णन नीचे किया गया है। इस प्रस्ताव में वेतन की तो सीमा है लेकिन लाभ या डिविडेंड की कोई सीमा नहीं है।

5. समता कर:- एक चमत्कारी कर जिस से देश दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करने की बजाय दिन दूनी रात सौ गुनी उन्नति करेगा और यह कर बैंक खातों में पड़े धन पर लगेगा। जो व्यक्ति कर को आधारीक संरचना /इंफ्रास्ट्रक्चर/ कल्याण / सामाजिक व धार्मिक कार्यों में लगाएगा तो उसका 95% तक उसको वापस कर दिया जाएगा और 5% बकाया में से उसे वेतन मिले जो 50% तक हो।

इंफ्रास्ट्रक्चर/ समाजिक व धार्मिक निर्माणाधीन कार्य समता कर के आधीन:- निम्न प्रबंधन – जल, वायु, वाहन, पर्यटन, ऊर्जा, गृह निर्माण, असहाय, कूड़ा प्रबंधन, कृषि, गांव व शहरी विकास, कुटीर उद्योग, सहकारिता, स्टेडियम, समाजिक कार्यों के लिए स्थान, प्रदूषण रोकने के लिए, चीजें व सेवाओं को मुफ्त बांटने के लिए कार्य, आजीविका प्रदान करने के लिए कार्य, अंतरजातीय व अंतर संप्रदाय विवाह इत्यादि के लिए।

समता कर की दरें:- 5 लाख रुपए तक कोई कर नहीं, 5 से 10 लाख रुपए तक ¼% प्रति वर्ष, 10 से 20 लाख रुपए तक ½% प्रति वर्ष, 20 से 50 लाख रुपए तक 1% प्रति वर्ष, 50 से 100 लाख रुपए तक 2% प्रति वर्ष, 100 से 500 लाख रुपए तक 5% प्रति वर्ष 500 से 1000 लाख रुपए तक 10% प्रति वर्ष, 1000 से 2000 लाख रुपए तक 20% प्रति वर्ष और 2000 लाख रुपए से ऊपर 25% प्रति वर्ष।

ऊपर लिखित के अतिरिक्त :-

1. करंसी नोटों के स्थान पर सिक्कों का चलन हो और 10 हजार रुपए से ऊपर रखने पर देशद्रोही माना जाए और उसकी सजा 10 साल काला पानी की हो यानि उसे 5000 किलो मीटर दूर तक भेज दिया जाए जहां पर उसे किसी भी अपने को मिलने ना दिया जाए। व
2. सेना व पुलिस के अतिरिक्त किसी के पास हथियार पाए जाएं तो वह देशद्रोही माना जाए और उसकी सजा मौत हो, जिससे एक आम आदमी की सुरक्षा बेहतर हो सके और प्रत्येक व्यक्ति निडर हो सके। जब किसी के पास हथियार होंगे ही नहीं तो सुरक्षा बेहतर ही होगी।

ऐसा होने पर देश के हालात इस प्रकार से होंगे :-

1. देश में गरीबी, भ्रष्टाचार व आतंक समाप्त होगा।
2. प्रत्येक व्यक्ति को भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा, पानी, बिजली व वाहन (ट्रांसपोर्ट) आसानी से उपलब्ध होगा।
3. समाज के प्रत्येक वर्ग विधार्थी, किसान, मजदूर, कर्मचारी व व्यापारी को उसकी योग्यता व सामर्थ्य के अनुसार अवसर मिलेंगे।
4. असहाय जिसमें अनाथ, बूढ़े व विकलांग आते हैं उनका जीवन खुशहाल होगा।
5. पढ़ाई, दवाई एक समान साधन सहित मुफ्त होगी। समय पर न्याय और ऐसी व्यवस्था जहां पर आरक्षण की आवश्यकता ही ना हो।
6. जल ठीक होगा, वायु ठीक होगी, जलवायु ठीक होगा, जिससे प्रत्येक नागरिक स्वस्थ रह सकेगा।
7. समाजिक बुराइयां कम से कम होगी।
8. देश की संपत्ति जो भूमि के नीचे होती है उसका बंटवारा सब को एक समान मिलेगा।
9. ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जहां पर केवल वह लोग राजनीति में आएंगे, जो वास्तव में देश की सेवा करना चाहते हैं। पुलिस मित्रवत, समयबद्ध न्याय और नौकरशाही प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए होगी।

जिस दिन भी ऊपर लिखित सुधार हो गए और उनको लागू कर दिया गया तो क्या होगा:- निम्नलिखित 95% से 100% कम हो जाएंगे:- आतंकवाद, माओवाद, गैंगस्टर, माफिया, ड्रग्स का व्यापार, महिलाओं व बच्चों की खरीद फरोख्त, स्मगलिंग, फिरौती, साइबर क्राइम, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, किडनैपिंग, मिलावट, सर्विलेंस, अन्यायिक व असमाजिक कार्य, भ्रष्टाचार, सट्टेबाजी, काला बाजारी, धोखाधड़ी के कार्य, मानव अंगों का व्यापार/ पेशवर खून देने वाले इत्यादि।

देश के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त होगा:- शुद्ध जल, शुद्ध वायु, अच्छा वातावरण/जलवायु, अच्छा भोजन, बेहतर स्वास्थ्य, चिंता मुक्त जीवन, जीवन में सुरक्षा, सम्मान पूर्ण जीवन, कम से कम प्रदूषण, आसानी से रोजमर्रा की आवश्यकता की पूर्ति, समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए आजीविका, भेड़ चाल नहीं, नए नए कार्यों को करने के अवसर, धन का मानवतावादी प्रयोग, मानवतावादी कर, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त, काम करने की इच्छा की भावना, समता, बेहतर क्षमता, नम्रता, आदर, अधिकार व अवसर, प्रत्येक व्यक्ति को मजबूत प्रजातंत्र और इन सब के ऊपर आजादी।

आजादी :- प्रत्येक व्यक्ति जब चाहे, जैसा चाहे वह आसानी से कर सके लेकिन समाज की परिधि व देश के नियमों के अनुसार। इसके लिए उसके पास समय, धन और साधन की जो आवश्यकता होती है तो यह सरकार की जिम्मेवारी है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता व सामर्थ्य के अनुसार उसको प्रदान करें, जिससे देश के प्रत्येक नागरिक को आदर, अधिकार व अवसर प्राप्त हो सके।

देश के हालात कैसे होंगे :- बहुत अधिक नौकरियां, कई गुना करो की आमद, पेंशन/बेरोजगार भत्ता प्रत्येक व्यक्ति को जिसका कोई आय का साधन नहीं है। आप जिस चीज के बारे में भी बात करें वह आसानी से उपलब्ध हो, धन का अर्थ ही समाप्त हो जाएगा और वह केवल बही खातों/चलन (Circulation) के लिए ही रह जाएगा। देश में किसी भी व्यक्ति को आरक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। प्रत्येक वेतन भोगी सप्ताह में 28 घंटे कार्य करने पर और सप्ताह में 7 दिन कार्य होने पर प्रत्येक व्यक्ति चिंता मुक्त व खुशहाल होगा।

कुंठा देश से समाप्त होना:- एक समान साधन सहित मुफ्त पढ़ाई होने पर, समय पर न्याय और आरक्षण की ऐसी व्यवस्था की आरक्षण की आवश्यकता ही समाप्त हो जाए से कुंठा का अंत होगा। कुंठा जो किसी भी व्यक्ति के मन में मोल की पढ़ाई, न्याय में देरी और आरक्षण के कारण पैदा होती है, यह कारण किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकते हैं और देश का उत्थान नहीं हो पाता।

आयकर समाप्त होने के बाद सरकार के पास धन कहां से आएगा ?

- उत्पाद शुल्क, बिक्री कर व सेवा कर लगने पर देश में करों की आमद बहुत बढ़ जाएगी और सिक्के चलने पर चोरी करना असंभव हो जाएगा।
- समता कर लगने पर जो व्यक्ति व्यापार या परियोजनाएं/प्रोजेक्ट्स नहीं कर पाएंगे उन पर यह कर लगेगा, उसकी आमद।
- सरकार 0.01% सालाना ब्याज पर ऋण/लोन ले सकेगी और यह 10, 20, 50..... 1000 लाख करोड़, जितना मर्जी हो लिया जा सकता है और यह केवल किताबी एंटी/लेखा-जोखा/चलन (Circulation) के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होगा और यह धन सरकार ने कभी वापिस भी नहीं करना होगा।
इस प्रकार सरकार के पास कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी।

अंत में :- देश का पैसा, देश के लिए, देश के द्वारा, देश के अंदर, देश के नागरिकों के लिए खर्च होगा ।

ऊपर लिखित प्रस्ताव के लागू होने पर निम्नलिखित घटित होगा:-

1. एक अमीर, मध्यम वर्ग व एक गरीब व्यक्ति आज से अधिक खुशहाल होगा और उसके जीवन में बेहतरी ही होगी ।
2. समाज के प्रत्येक वर्ग को अवसर ही अवसर प्राप्त होंगे और आजीवका के लिए एक विधार्थी, किसान, मजदूर, कर्मचारी व व्यापारी /स्वयं रोजगार करने वाले को अवसर ही अवसर होंगे ।

यहां पर हम एक बात कहना चाहते हैं और वह है असहायों (असहायों में अनाथ, बूढ़े व विकलांग आते हैं) जो ऊपर लिखित इन पांच वर्गों में से किसी ना किसी एक पर निर्भर करते हैं और जब तक उनका जीवन अच्छा नहीं होता तब तक असहायों का जीवन भी अच्छा नहीं हो सकता । आज देश में प्रत्येक वर्ग के जीवन के जो हालात हैं वह चिंताजनक है और ऐसे में असहायों का जीवन आराम देह व अच्छा नहीं हो सकता । इस प्रस्ताव के लागू होने पर समाज का प्रत्येक वर्ग खुशहाल होगा और विशेष तौर पर असहाय ।

3. समाज के प्रत्येक वर्ग को रोजमर्रा की जीवन की आवश्यकताएं आसानी से प्राप्त होगी जैसे कि भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा, पानी, बिजली व ट्रांसपोर्ट /वाहन इत्यादि ।
4. इससे समाज में, देश में **समता आएगी** जिससे उनकी **क्षमता बढ़ेगी** और उसके साथ-साथ **नम्रता भी आएगी**, जो देश के उत्थान के लिए अति आवश्यक है ।
समता:- समता का अर्थ यह नहीं है कि सब एकदम बराबर हो लेकिन यह व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता व सामर्थ्य के अनुसार होनी चाहिए । लेकिन जिस व्यक्ति के पास क्षमता व सामर्थ्य में कोई कमी है तो उसे भी रोजमर्रा की आवश्यकताएं आसानी से उपलब्ध हो जिसका वर्णन उपर किया गया है ।
5. इस व्यवस्था के लागू होने पर देश के प्रत्येक नागरिक को आदर, अधिकार व अवसर प्राप्त होंगे ।

श्री परमधाम, मेरठ

अधिक जानकारी के लिए कृपा वेबसाइट देखें :- www.solutionoflife.in

प्रजातंत्र के स्तंभ

संसदीय प्रजातंत्र

1. विधायिका - नेतागण
2. कार्यपालिका - पुलिस व नौकरशाही (ब्यूरोक्रेसी)
3. न्यायपालिका - न्यायधीश इत्यादि

मजबूत प्रजातंत्र की स्थापना कैसे हो सकती है ?

राजनीतिक सुधार

1. प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का चुनाव सीधा जनता के द्वारा हो ।
2. सांसद /एम. पी. व विधायक /एम. एल.ए. की पेंशन उस के वेतन के बराबर हो और उनकी आमदनी का और कोई अन्य साधन ना हो ।
3. यदि किसी व्यक्ति के पास चल व अचल संपत्ति है (स्वयं, पति /पत्नी या अव्यस्क बच्चे) तो वह संपत्ति देश को दान की जाए ।

पुलिस के सुधार

1. देश में पुलिस कर्मियों के लिए सप्ताह में 28 घंटे का कार्य हो। आज पुलिस कर्मियों का कार्य 24 x 7 का होता है, जिससे उनकी सेहत को बहुत हानि पहुंचती है ।
2. वेतन दोगुना हो । और
3. जिनका पेट बेल्ट से बाहर आए वह स्वयं इस्तीफा / त्यागपत्र दे । उनको इसे ठीक करने के लिए 6 महीने से 12 महीने का समय दिया जाए ।

न्यायिक सुधार

1. प्रत्येक मुकद्दमे की समय सीमा निर्धारित हो जो उसकी प्रवृत्ति पर निर्भर करें । जैसे कि चेक वापसी (डिसऑनर), एक सूनवाई या एक महीना जो दोनों में से कम हो ।
2. प्रत्येक 5 जिलों में एक हाई कोर्ट का बेंच हो, प्रत्येक 5 राज्यों में एक सुप्रीम कोर्ट का बेंच हो।
3. जितने भी पुराने मुकद्दमे हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाए ।

नौकरशाही (ब्यूरोक्रेसी) : नौकरशाही के बारे में यह कहा जाता है कि उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती । जब ऊपर लिखित राजनीतिक व्यवस्था, पुलिस व न्यायिक व्यवस्था ठीक हो जाएगी तो नौकरशाही स्वयं अपने आप ठीक हो जाएगी यानि हम उनको जैसा चाहे वैसा मोड़ पाएंगे ।